

# छोटी सोच वालों के कारण आईआईटी खाली करना पड़ा : आईआईटी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

आईआईटी ने साढ़े पांच साल तक देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के आईआईटी कैम्पस में किराएदार रहने के बाद ब्लॉक खाली कर दिया है। हालांकि इस संबंध में आईआईटी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डीएवीवी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग, कलेक्टर व अन्य संबंधितों को पत्र भेजा है। इसमें राज्य शासन की नीति, यूनिवर्सिटी और आईआईटी प्रबंधन को कोसा है। इसमें लिखा है कि आईआईटी के प्रशासनिक अधिकारी परेश



अत्री जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण आईआईटी ने कैम्पस छोड़ा।

आईआईटी रजिस्ट्रार डॉ. ए.आर. सुब्रह्मण्यम ने पत्र में लिखा है कि इंदौर के

साथ देश में सात अन्य आईआईटी खोले गए, लेकिन किसी भी आईआईटी प्रबंधन को कैम्पस के लिए किराया नहीं देना पड़ा। केंद्र के साथ राज्य सरकार ने तय किया था कि वह आईआईटी को मुफ्त जमीन देगी। जब तक कैम्पस नहीं बन जाता, अस्थायी जगह दी जाएगी लेकिन मप्र सरकार ने इसका किराया लिया। अतिरिक्त किराए के लिए यूनिवर्सिटी ने हमसे कहा आईआईटी ज्यादा जमीन पर संचालित है। हमने पांच साल में कई बार यूनिवर्सिटी को लिखा कि मिलकर नपती करवा लेते हैं, लेकिन नहीं सुनी।

**हम भी वॉल पेपर, पेड़ ले जाएं क्या**

पत्र में लिखा गया कि कहा जा रहा है आईआईटी ने आईआईटी के ई और एम ब्लॉक को नुकसान पहुंचाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने यहां रोड बनवाई। पेड़ लगवाए। फॉल सीलिंग कराई। विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाई। वॉल पेपर लगवाए। क्या हम इन्हें अपने साथ ले जाएं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका उपयोग सभी करेंगे। आईआईटी प्रबंधन और पदाधिकारियों ने आईआईटी की छवि गिराने की कोशिश की है, जिससे संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह गए।

**पत्र मिला है, मैं कुछ नहीं कहूंगा**

आईआईटी का पत्र मिला है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता।

- डॉ. संजीव टोकेकर, डायरेक्टर आईआईटी  
**मैंने सिर्फ अपना काम किया**

आईआईटी के प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैंने सिर्फ अपना काम किया। कभी आईआईटी प्रबंधन से सीधे बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या और क्यों लिखा।

- परेश अत्री, प्रशासनिक अधिकारी आईआईटी